



# भारत का चाज़ीपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—कण्ठ 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

का.

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, विसम्बर 3, 1992/अग्रहायण 12, 1914

No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1992/AGRAHAYANA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

न्यू बैंक ऑफ इंडिया

(कार्मिक विभाग)

भ्रष्टाचारा

मई दिल्ली, 3 विसम्बर, 1992

सं. 5014/92—बैंकारी कानूनियों (उपक्रमों का आज्ञन  
और अन्तर्गत) अधिनियम 1980 की आरा 19(1) द्वारा प्रवत्त  
भ्रष्टाचारों का प्रयोग करते हुए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का निवेशक नंदल,  
रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण मंजूरी  
से एतद्वारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी सेवा विनियम 1982  
के निम्नलिखित विनियमों में पृष्ठ संख्या करता है :-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन विनियमों को न्यू बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा  
(संशोधन) विनियम 1987 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की रियि से लागू  
होंगे।

3. विनियम 20 में संशोधन

सेवा का परिवर्गा

20(1) (क) विनियम-16 के उपनियम-(3) के भ्रष्टाचारी  
बैंक को यह संज्ञित हो जाए कि किसी अधिकारी  
का कार्यनिवारण भ्रष्टाचारक या अपराधित है या  
उसकी ईमानदारी पर वास्तविक रूप से संदेह  
हो, या बैंक को सेवा में उसकी विचारान्तरा बैंक  
हितों के प्रतिकूल हो, एवं अहो अनुशासनिक  
प्रक्रिया के अनुसार उसके विश्वास तुरत कार्यवाही  
करना सम्भव न हो वहाँ बैंक तीन महीने का  
नोटिस देकर या उसके बादतो में सरकार द्वारा  
सरकार पर जारी मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार  
तीन माहों की परिलिखियाँ देकर उसकी सेवाएं  
ममाल कर सकता है।

(थ) इस उप विनियम के भ्रष्टाचारी सेवा समाप्ति  
के आदेश तब सक न जाए कि ऐ जब तक  
नि ऐ अधिकारी को प्रसातित आदेश के विश्वास  
बैंक द्वारा निवेदन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान  
न किये जायें।

- (ग) उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सेवाये समाप्त करने का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रशंसन निदेशक द्वारा ही लिया जायेगा।
- (घ) अधिकारी कर्मचारी को उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत प्रतिविधि विनियम के विषय में अधिकारी को अधिकार देता, यदि वह बैंक के निवेशक मंड़न को 15 दिन के अन्वर अपील प्रस्तुत कर दे। यदि प्रोत्तर स्वीकार कर ली जाये तो उप विनियम (क) के अन्तर्गत विवेदीय आदेश रद्द समझे जायेंगे।
- (इ) इहाँ किसी अधिकारी कर्मचारी की सेवाये समाप्त कर दी गई हों एवं जिसे नोटिस के बदले तीन माह की प्रतिविधियों का भुगतान कर दिया गया हो ऐसे अपील के पक्षकात सेवाये समाप्ति के आदेश रद्द कर दिये जायें तो नोटिस के बदले में भुगतान की गई राशि का सम्मोहन उसे दिये जाने वाले वेतन से किया जायेगा यदि, उसकी सेवाये समाप्त न की जाती और उसे वेतन दिया जाता तथा जो उसकी सेवाये समाप्ति के आदेश पात्र न होने की विधि में समान विधम एवं अर्ती के आधार पर बैंक गोजाता में रहने की विधि में उससे प्राप्त होते।
- (ख) कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी सेवाये उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई है उसे उपदान, भविष्य निधि सहित नियोक्ता का अंशदान एवं सेवा अधिक के दौरान नियमानुसार स्थायी समस्त अन्य देयताओं का भुगतान किया जायेगा।
- (ड) उपरोक्त वर्णित तथ्यों के बावजूद विनियम 19(1) के अन्तर्गत बैंक को किसी भी अधिकारी की सेवा निवृत्त करने का अधिकार प्राप्त होता।

20(2) कोई अधिकारी बैंक की गोदानों को छोड़ने परथवा पर्याप्ति करने की अपनी प्रवत्त्याग्य के संबंध में कोई पूर्णांकित सूचना दिये और बैंक न तो नोटों छोड़ेगा और उसके जवाब पर्याप्ति करेगा। इसके विषये नोटिस की प्रतिविधि 3 माह होती और यह नोटिस इत्य विनियमों में उल्लिखित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु राजस्व प्राधिकारी 3 माह की नोटिस अधिक तथा नोटिस देने की व्यवस्था का परिवर्तन कर सकता।

20(3) (1) ऐसा अधिकारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यालय लिंबित चल रही है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्णांकित भविष्यत लिये बैंक वी सेवा यो छोड़ने/पर्याप्ति करने परथवा अनुपम नहीं दें सबैभा, तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यालयों से पूर्ण प्रथवा इसके दौरान दिये गये जिनी शायद तथा नोटिस का तब तक कोई प्रभाव नहीं रहेगा जब तक कि इसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर दिया गया हो।

(ii) इस विनियम के प्रयोगान्वय विभी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यालयों को जा नह नोटिस माना जाएगा, यदि उसे नियंत्रणाधीन किया गया हो तथा उसे इस आजग का कोई कारण तताओं नोटिस दिया गया हो कि, यांत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यालयों की जाए एवं इसे तब तक लंबित माना जाएगा; जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश परियां नहीं रहती।

(3) कोई भी अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यालयों की आरम्भ कर दी गई है की नियंत्रण तिथि सेवाएं समाप्त हो जाएगी किंतु अनुशासनिक कार्यालयों उपरी प्रशासन द्वारा रहेगी औसतीकरणीय जारी रहने के दौरान जारी रहती, जब वक्त के अन्यालयों में समाप्त नहीं हो जाती एवं इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं किए जाते। संबंधित अधिकारी नियंत्रण की विधि के पश्चात से कोई नियंत्रण और/या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। वह कार्यालयों पूर्ण होने तक तथा अंतिम आदेश जारी किए जाने तक भविष्यत में से प्रपत्ते अंशदान के अंतिरिक्त सेवानिवृत्ति लात प्राप्त करने का भी पाल नहीं होगा।

#### विनियम 20(1)(क) के अन्तर्गत मार्गदर्शी निर्देश

किसी भी अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के विकल्प का अधीन वेतन वही किया जाएगा जहाँ:

- (1) विभी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारी की हसियत ऐसा निर्णय लेने पर जिससे बैंक को आर्थिक हानि हो, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई दुरावरण सिद्ध न कृप्ता हो।
- (2) कोई भी अधिकारी कर्मचारी, यदि किसी भी कारण से 90 दिन से अधिक समय से लातार ब्यटी से अनुपस्थित रहता हो और यह उसको नवाचार पुरियां का समाप्त कर चका हो एवं अधिकारी उसके अनुरोध को निवित रूप में अस्वीकार कर दिया गया हो।
- (3) कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसे किसी विशिष्ट कुशलता या नियुक्ति या योग्यता के कारण नोटिस द्वारा प्रदान किया गया हो एवं किसी भी कारण से उसकी ऐसी नियुक्ति या कुशलता या योग्यता समाप्त हो जाए।
- (4) अधिकारी कर्मचारी को नवाचार तीन वर्षों से अधिक कार्यालयान्वयन मूल्यांकन में यातार निर्णय के अंतर्गत औरत से कम अंक प्राप्त हों हों एवं प्रथम दो वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में उसे मूल्यांकित किए जाने के बावजूद भी उसमें कोई नुस्खार न हो रहा हो या कार्यनिष्पादन में अप्रयोगित सुधार पाया गया हो।
- (5) नियंत्रण ऐसी हो कि उपद्रव, विद्वान् या सामाज्य अनुशासन-नियंत्रण अवकाश के कारण अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध शावकारी वायरां रहना संभव नहीं है।
- (6) दुरावरण को शिद्ध करने वाले विश्वसनी प्रमाण नष्ट हो जाय, या नवृत्त गयाह उपनियम न हो सकते हों तथा इस पर प्रबंधक वर्षों का कोई नियंत्रण न हो।
- (7) ऐसा कोई जन्य कारण है जिससे बैंक को यह विश्वास हो जाए कि अधिकारी कर्मचारी को सेवा में रोके रखने से बैंक हितों पर प्रतिफूल प्रभाव पड़ता है।

**NEW BANK OF INDIA**

(Personnel Department)

**NOTIFICATION**

New Delhi, 3rd December, 1992

No. 5014/92.—In exercise of the powers conferred by Section 19(1) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1980, the Board of Directors of New Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Govt. hereby makes the following Regulations further to amend New Bank of India Officers' Service Regulations, 1982.

**2. Short Title and Commencement :**—(i) These Regulations may be called New Bank of India Officers' Service (Amendment) Regulations, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**3. Amendment to Regulation 20 :—****Termination of Service —**

20(1) (a) Subject to sub regulation 3 of Regulation 16, where the bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafide suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudicial to the interest of the bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the bank may terminate his services on giving him 'three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Govt. from time to time.

(b) Order of termination under this sub regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the bank against the proposed order.

(c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman & Managing Director.

(d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.

(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months' emoluments in lieu of notice and on arrears his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the bank's employment on the

same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.

(f) An officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered.

(g) Nothing contained hereinabove will affect the bank's right to retire an officer employee under Regulation 19(1).

20(2) An officer shall not leave or discontinue his service in the bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be three months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations.

Provided further that the Competent Authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.

20(3) (i) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave, discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of Competent Authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or an notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him, and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(iii) The Officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contribution to CPF.

**Guidelines under Regulation 20(1)(a)**

"The option to terminate the services of an officer shall be exercised only where :

- (i) Decision taken by the officer employee in his capacity as an officer employee has put the bank to monetary loss though no misconduct as such can be proved against him;
- (ii) The officer employee for any reasons, has not been attending to his duties in the bank continuously for a period of 90 days after exhausting all leave due to him or after his request for extension of leave has been refused in writing.
- (iii) The Officer employee employed on the basis of a particular expertise or skill or qualification, ceases to possess such an expertise or skill or qualification, for any reasons whatsoever;

- (iv) The Officer employee, for three consecutive years in annual appraisal of his performance, has received ratings of less than average and despite the appraisal reports of the first two years having been communicated to him there has been no improvement or insufficient improvement in his performance.
- (v) Situation is such that due to violence, insurgency or general indiscipline, insubordination, holding an enquiry against the officer employee is not possible.
- (vi) The evidence to be relied upon to prove the misconduct gets destroyed or the principal witness(es) becomes unavailable for reasons beyond Management's control.
- (vii) There is such other cause as would reasonably lead the bank to believe that the retention of the officer employee would prejudice the bank's interests."

**KHUSHAL SINGH, Asstt. General Manager (P)**